Tsunami Evaluation Coalition:

Impact of the sunami response on local and national capacities

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना :

सूनामी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में सूनामी मूल्यांकन दल (टीईसी) ने पांच सामानान्तर मूल्यांकनों का प्रारंभ किया, जिसमं से यह एक है । इस मूल्यांकन का उद्देश्य सूनामी प्रतिक्रिया का प्रभाव निश्चित किना था, मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों/कार्यकर्ताओं की भूमिका, सहायता एवं रिकवरी के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता और जोखिम को कम करना था । टीओआर ने निम्न छः उद्देश्यों का पता लगाया :

- सूनामी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप स्थानीय एवं राष्ट्रीय क्षमता में कैसे परिवर्तन आता है, इसका निर्धारण करना ।
- सहायता एवं रिकवरी मे मदद उपलब्ध कराने में कितनी अच्छी तरह अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को स्थानीय एवं राष्ट्रीय क्षमता के साथ लगाने का निर्धारण ।
- सूनामी की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की स्थानीय एवं राष्ट्रीय क्षमता में ऐच्छिक व अनैच्छिक परिवर्तनों का निर्धारण ।
- किस सीमा तक पारगमन परिवर्तन/जोखिम में कमी/रिकवरी कार्यक्रम, नियोजित एवं कार्यान्वित स्थानीय एवं राष्ट्रीय क्षमता को प्रभावित करने का निर्धारण ।

- भावी संकटों की प्रतिक्रिया एवं उबरने के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने का प्रयास ।
- उपरोक्त समस्त निर्धारण एवं लिंग भिन्नता व स्त्री तथा पुरूष के विविध अनुभवों को आवश्वस्त करना ।

चार प्रभावित देशों-इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालद्वीप और थाईलैंड ने मध्य सितंबर 2005 और मध्यन नवंबर 2005 के बीच क्षेत्रीय अध्ययन की बीड़ा उठाया । तीन अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की एक टीम ने चारों देशों का अध्ययन किया जिसमें मालद्वीप के लिए अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहायता साथ थी । इंडोनेशिया, श्रीलंका एवं थाईलैंड में राष्ट्रीय परामर्शदाताओं ने इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान की । दावाधारकों के विचारों की संरचना सर्वेक्षण का कार्य एसिह(इंडोनेशिया) और श्रीलंका में किया गया ।

इस मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु, 'क्षमता' शब्द को बृहत आश्य के साथ लिया गया- जैसे तकनीकी कौशल से अधिक अनुदार, सेवाओं एवं कार्यक्रमों को चलाने के लिए योग्यता का घेराव, नीतियां एवं लंबी सीमा की रिकवरी व पुनःनिर्माण की कार्यसूची और सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं की जबावदेही ठहराना । इसमें वे सभी प्रतिक्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा इन परिणामों को प्राप्त करना है, विशेष रूप से भाग लेने की क्रिया, परामर्श एवं सूचना में हिस्सेदारी । मूल्यांकन का यह प्रयत्न नहीं होता कि वह किसी विशिष्ट एजेंसी का प्रदर्शन/संपादन का मूल्यांकन करे, अपितु समग्र

घटों को केंद्रीभूत करे तथा सबको लेकर मिली प्रतिक्रिया से सबक निकाले । टीम मानती है कि संपादन में विस्तीर्ण विविधता है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो देखे गए सामान्य झुकाव के अपवाद हो सकते हैं ।

राष्ट्रीय एवं स्थानीय क्षमता

राष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड प्रतिक्रिया के प्रबंधन में सफल था, उसके भली प्रकार बनाए गए ढांचे एवं योजनाएं थीं । शासकीय अस्तित्व के मध्य समन्वय के अभाव में इंडोनेशिया व श्रीलंका में स्थिति बिगड़ी थी, जब कि मालद्वीप में प्रारंभ में त्वरित एवं प्रभावित प्रतिक्रिया थी, लेकिन बाद में बर्हिवर्ती समुदाय के प्रतिनिधित्व में कमी आ गई । इन चार देशों में अतिकेंद्रीयकृत नियंत्रण की प्रवृति के कारण स्थानीय प्रशासन में कठिनाईयां आने लगीं । अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भावी आपदा की तैयारी हेतु विशेष रूप से श्रीलंका, मालद्वीप व थाईलैंड में राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत किया । इंडोनेशिया में राज्य ने राष्ट्रीय नीति एवं क्षमता में महत्वपूर्ण विकास का प्रारंभ किया, जिन्हें अभी सिद्ध करना शेष है । सम्पूर्ण इलाके में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आंतरिक विस्थापित लोगों में अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर भी हमेशा की तरह वांछनीय परिणाम नहीं निकले । लेकिन स्थानीय एवं राष्ट्रीय सरकार की अंतःक्रिया कठिनाईप्रद रही ।

सामुदायिक स्तर पर परिणाम कम धनात्मक हैं । मूल्यांकन से यह पता चला कि सूनामी प्रतिक्रिया में स्थानीय स्वामित्व की कमी थी एवं कुछ स्थानीय क्षमताओं ने आपदा की प्रतिक्रिया द्वारा और अधिक आघात पहुंचाया । यद्यपि श्रीलंका के

सर्वेक्षण से प्रारंभ में प्रतिक्रिया की सामान्य धनात्मक दर प्रकट होती थी जो समय के साथ बाद में कम हो गई । क्षमता से संबंधित समस्या का तब पता चला जब ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार से दावाधारकों के कौशल का इस्तेमाल किया गया उसमें से केवल 20 प्रतिशत दावाधारक ही संतुष्ट थे, जब कि लगभग आधों ने इस कार्य में अपनी नियुक्ति को असंतोषजनक एवं व्यर्थ पाया । सर्वेक्षण से प्रतिक्रिया में निष्पक्षता की कमी का बोध होता है । स्त्री प्रमुख एवं गरीब परिवार के लोगों को अधिक हानि हुई, जब कि जो अधिक स्पष्टवक्ता थे उन्होंने अधिक फायदा प्राप्त किया । यह प्रवृति धीर-धीरे बढ़ती हुई प्रतीत होती है । सहायता अवस्था के दौरान सीमांत समूहों को मदद प्रदान की गई, लेकिन अपने अधिकारों एवं आम सेवाओं को प्राप्त करने की अयोग्यता के कारण और सूचना व संगठन की कमी के कारण इन्हें उत्थान एवं पुनर्निर्माण की अवस्था में नजरअंदाज कर दिया गया । उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं एवं चिंताओं को अधिक अग्रसक्रियता एवं रणनीति की प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी ।

(कम से कम श्रीलंका में) सामान्य प्रतिक्रिया में स्त्री को पुरूष की अपेक्षा संतुष्टि स्तर में निकृष्ट माना गया है । यह सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिक्रिया में ध्यान की कमी को दर्शाता है । इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय सफलताएं हैं, लेकिन सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने स्त्री को उतनी सुरक्षा प्रदान नहीं की जितनी उनको करनी चाहिए थी । इसमें सबसे अधिक आघातपूर्ण वे हैं जो अलग-अलग कुछ कारणों से सीमांत पर हैं, विशेष रूप से संघर्ष एवं वे स्त्रियां जो कैम्प में हैं ।

जिन स्त्रियों के पास सूनामी से पहले कुछ संपत्ति थी उनको पुरूषों की अपेक्षा कम क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई जब कि ऐसे पुरूषों के पास पहले ही कई संपत्तियां थीं । विशिष्टतः यह जीवनयापन में सहायता के मामले में भी सत्य है ।

जाति स्तर पर अंतर्निहित ये समस्याएं प्रारंभिक चरण में जाति पर आधारित संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों (सीबीओ व एनजीओ) के साथ जुड़ने की कमी के कारण थीं । इनमें से बहुत ने छानबीन एवं मुक्ति/बचाव की अवस्था के दौरान मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन सहायता प्रक्रिया के दौरान ये सीमांत हो गई थीं, रिश्तों में तनाव आ गया था अथवा क्षमता कमजोर पड़ गई थी, समय के साथ उन एजेंसियों ने रिकवरी अवस्था में उनका सहयोग प्राप्त कर लिया ।

इस प्रतिक्रिया के पहलुओं में एक सबसे सफल पहलू समुदायों व व्यक्तिविशिष्ट में उनकी इच्छा के अनुसार सामग्री वितरण की अपेक्षा के साथ नकद अंतरण को मान्यता प्रदान करना था । एसिह सर्वेक्षण में 90 प्रतिशत सर्वेक्षणों से महसूस हुआ कि भोजन एवं अन्य सहायता प्रदान करने वाली वस्तुओं से अच्छा नकदी है । श्रीलंका के बहुसंख्यक लोगों (53 प्रतिशत) ने भी सामान की अपेक्षा नकदी को पसन्द किया, जिसे अन्य 12 प्रतिशत उन लोगों ने भी समर्थन प्रदान किया जो यह अनुभव करते थे कि नकदी से वे वह खरीद सकते हैं जो वे चाहते थे ।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में विशेषांक

प्रतिक्रिया का विशिष्ट पहलू जिसने स्थानीय क्षमता को दुर्बल करा दिया उसमें अन्य संगठनों से कर्मचारियों का अतिक्रमण, विशेष रूप से स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों

और सूचनाओं के लिए कष्टदायक आवश्यकताएं शामिल हैं । गति एवं पार्श्वक पर बहुत जोर दिया गया था, मुख्य रूप से निष्कासित कर्मचारियों का अनावश्यक एवं अपव्ययी प्रयोग, जिनमें थोड़ा संबंधित अनुभव था और इलाके में अति जटिल सामाजिक ढांचे के समुदाय को विशिष्ट हानि थी । संरचनात्मक ढंग से यह स्थानीय क्षमता के निम्न अनुमान को दर्शाता है जो सामन्य रूप से बहुत सी तत्काल समस्याओं का व्यवहारक था । सभी चार देशों का निष्कर्ष यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहायता आने से पूर्व ही स्थानीय समुदाय ने जीवन बचाने का कार्य कर दिया था । उन्हें रिकवरी की स्थिति में समर्थन की आवश्यकता था । इन प्रारंभिक त्रुटियों ने लम्बे समय में अंतर्राष्ट्रीय सहायता के रिश्तों में समर्थन एवं प्रभावोत्पादकता व कुशलता का विकास किया । अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने स्थानीय क्षमताओं को दुर्बल कर दिया और लम्बे अंतराल की रिकवरी को अधिक मुश्किल कर दिया । तत्काल सहायता प्रदान करना अथवा स्थानीय क्षमताओं के साथ जुड़ना इन दोनों में सही संतुलन बैठाना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन इस मामले में संभवतः धन को तेजी से खर्च करने के दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उतावली थीं ।

निष्कर्ष

शक्ति के मामले में क्षमता को पृथक नहीं किया जा सकता । एक समाज जो असमानता और सीमांतता जैसे मामलों का प्रभावी रूप से स्वयं प्रबंधन करता है वह आपदाओं का सामना भी अच्छी तरह कर सकता है । स्थानीय क्षमता का तात्पर्य

केवल सहायता देना ही नहीं है, अपितु आपदा शान्ति में लम्बे समय तक उसकी भूमिका है । लेकिन यह एक सरल मामला नहीं है, बहुत से देशों में सामाजिक विभाजन एवं विरोध की गंभीर समस्याएं हैं । इस प्रकार के समाज में क्षमता निर्माण इतना सहज नहीलं है, बल्कि इसमें जटिल राजनैतिक प्रक्रिया जिसमें गरीबों को शक्ति, वर्जित लोगों का शामिल होना है जिससे जब भी आपदा आती है उनके पास उनके समुदाय, स्थानीय लोगों एवं राष्ट्रीय सरकार के लिए वैध दावा होता है ।

इस परिप्रेक्ष्य में सूनामी प्रतिक्रिया का निर्धारण केवल सामान एवं सेवाओं के देने से ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे भी करना चाहिए कि क्या इसे स्थानीय क्षमताओं का समर्थन प्राप्त है, विशेष रूप से सीमांत समूहों का । लेकिन यह सदैव अंकित नहीं होता और प्रायः सहायता के सामाजिक प्रभाव का एजेंसियों को भी पता नहीं होता । क्षमता की मजबूती की स्वयं में भी इसकी अच्छी मान्यता होनी चाहिए । क्षमता की मजबूती की महत्ता इससे भी है कि यह आपदा प्रतिक्रिया की धारणीय पहुंच का प्रतिनिधित्व करती है । इसका लाभ लम्बे समय में आपदा के शमन एवं निवारण तथा तत्काल आवश्यकताओं पर ध्यान देने से प्राप्त होता है ।

क्षमता मजबूती की महत्ता मानवीय प्रतिक्रिया के निर्देशक सिद्धान्त के रूप में मान्य है फिर भी इसे स्पष्ट एवं पर्याप्त रूप से आपदा शमन के साथ नहीं जोड़ा गया है । यह मूल्यांकन मानवीय कार्यकर्ताओं की नीतियों और स्थानीय क्षमता और समुदाय की भागीदारी के साथ सीधे निष्पादन एवं तत्पर होने के रूप में परिचालन

वास्तविकताओं के मध्य विषमता पर प्रकाश डालता है । संकटों की दशा में जब सहायता तंत्र दबाव में हो, तब प्रबलता से सेवाएं प्रदान करना अत्यावश्यक है-सूनामी प्रतिक्रिया होने के कारण संभवतः यह एक उत्तम उदाहरण है ।

अनिवार्यतः अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुख्यालय से 'परिणामों' के लिए कड़ा दबाव है । लेकिन क्षेत्रीय कर्मचारियों में स्थानीय क्षमता को कम अनुमानित कर बाहरी सहायता को अत्यधिक महत्व देने की सामान्य प्रवृति है । यह वह प्रक्रिया है जिसकी पुनः पुष्टि करनी है । स्थानीय क्षमता की उपेक्षा कर बाहरी सहायता की भूमिका को अधिक महत्व का मानना अधिक महत्वपूर्ण है । अधिक बाहरी सहायता से स्थानीय क्षमता दुर्बल होती है । इसमें बाधा यह होती है कि रिकवरी अवस्था में संबंधों एवं रणनीति के विकास में असफलता प्राप्त होती है । प्रतिक्रिया लगभग छः माह के लिए रूक जाती है, जैसा कि सूनामी आपदा के मामले में हुआ ।

मानवीय सहायता के अंतिम लक्ष्य एवं सेवाएं देने कह पहुंच से क्षमता को शक्तिवान बनाने की रूपरेखा की ओर जाने की आवश्यकता पर पुनःविचार करने की जरूरत है, अथवा अन्य शब्दों में सुपुर्दगी से समर्थन व सरलीकरण की ओर मुड़ने पर जोर देना ।

व्याख्यान संदेश

मूल्यांकन टीम के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के ध्यान हेतु 3 व्याख्यान क्षेत्रों का पता लगाया है इनमें सभी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डों से संबंधित हैं, लेकिन इस

मूल्यांकन के आधार पर जिन क्षेत्रों में सूनामी प्रतिक्रिया कमजोर हुई है वे भी प्रयोग में हैं ।

-स्थानीय एवं राष्ट्रीय क्षमताओं के साथ जुड़ना

इसमें ऐसी योग्यता शामिल है जिससे स्थानीय क्षमता को मान्यता देकर पहचाना जाए और भागीदारी व परामर्श के द्वारा स्थानीय क्षमताओं को योजनाओं व निर्णय लेने में शामिल करने की आवश्यकता है और जहां तक संभव हो सके निर्णय लेने की प्रतिबद्धता को विकसित किया जाए ।

-सामाजिक असमानताओं, अपवर्जन एवं पदसोपान की ओर ध्यान

क्षमता को केवल कौशल एवं प्रशिक्षण के संबंध में ही परिभाषित नहीं करना चाहिए अपितु गरीबों और सीमांत समूहों को भी शक्तिवान बनाने के रूप में करना चाहिए । आपदा के सामने डटकर रहना समुदान की क्षमता की संवेदनशीलता है । इसमें सरलता से केवल ऐसे समूहों का पता लगाना ही शामिल नहीं है, अपितु विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय लेने में उनकी आवाज सुनी जा रही है ।

स्वीकृत वातावरण व प्रासंगिक योगदान

जाति के संदर्भ में सीमांत समूहों की स्थिति और जातियों के संदर्भ में जिला व राष्ट्रीय प्राधिकार में सुधार की आवश्यकता है । इस प्रक्रिया के आधार में सूचना की रणनीति प्रबंधन व निम्न स्तर की जबावदेही को मजबूत करने के द्वारा शक्तिवान बनाना है । पक्ष समर्थन भी इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है लेकिन ये बाहरी हस्तक्षेप के बजाय स्थानीय शक्तियों को बढ़ाने पर आधारित होना चाहिए ।

अनुशंसाएं

विशिष्ट देशों की अनुशंसाओं के लिए कृपया व्यक्तिगत रिपोर्ट सारांश का संदर्भ लें जिन्हें परिशिष्ट में प्रस्तुत किया गया है । उक्त अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए उक्त व्याख्यान संदेश का निम्न सामान्य अनुशंसाओं में अनुवाद किया गया है ।

अतिप्रभार अनुशंसा

भूमंडलीय स्तर पर विस्तृत क्षेत्रों की चर्चा प्रारंभ होनी चाहिए जिसे मानव क्षेत्र के आधारभूत पूर्वाभिमुखीकरण को संबोधित करने की आवश्यकता है एवं जो मानवीय सहायता का स्वामित्व दावाधारकों के पास होने के सिद्धांत पर आधारित हो । इसमें सुपुर्दगी से समर्थन एवं सरलीकरण की ओर मुड़ने पर जोर देना निहित है । इस प्रकार की चर्चाओं से निम्न अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की आशा होती है ।

अनुशंसा-1 स्थानीय एवं राष्ट्रीय क्षमताओं के साथ जुड़ना

-अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पहले से ही समस्याओं के लिए तैयार रहना चाहिए केवल साधनों का पता लगाकर ही नहीं अपितु अपने तंत्र में स्थानीय लोगों व राष्ट्रीय सरकारों की अधिकाधिक भागीदारी द्वारा ।

-उन्हें योजनाओं को बड़ी आपदा के दौरान और अधिक सामूहिक कार्य करने के ढंग से बनाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि वे अपनी क्षमता से परे उसे नहीं बढ़ाएंगे, अपितु अन्यों के साथ जुड़कर अपनी भूमिका को बांटना चाहिए ।

-उनकी साझेदारी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए और स्थानीय साझेदारी को शुरू से ही

विकसित करना चाहिए जिससे सहायता से रिकवरी तक आसानी से पहुंचा जा सके ।

-उन्हें ऐसी कार्यविधि स्थापित करनी चाहिए जिससे बिना हस्तक्षेप के लम्बी समयावधि हेतु अनुदान दिया जाए एवं उनके द्वारा सूचित की गई आवश्यकताओं पर आलोचनात्मक रूप से जांच होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि वे सीबीओ के विरूद्ध नहीं हैं ।

-कर्मचारियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए विशिष्ट समझौते व नयाचार/संलेख बनाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि स्थानीय क्षमता दुर्बल नहीं हुई है ।

अनुशंसा-2 : सामाजिक असमानताओं, अपवर्जन एवं पदसोपान की ओर ध्यान

-ऐसी रणनीति विकसित होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि स्त्रियों एवं सीमांत समूहों को पूरी तरह सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं ।

-स्त्री दावाधारकों को ऐसे सभी निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो उन्हें प्रभावित करते हैं ।

-योजना इस पूर्वानुमान पर आधारित होनी चाहिए कि यदि सुधार का कार्य नहीं किया गया तो समुदाय की असमानता को सहायता द्वारा मजबूत किया जा सके ।

-योजना बनाते समय सामुदायिक ढांचे की जटिलताओं का ध्यान भी रखना चाहिए तथा परिणामस्वरूप निर्णयों को प्रभावित करने के जानकर स्थानीय मध्यस्थों की शक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए ।

-सबसे अधिक सीमांत लोगों को शामिल करने को आधारभूत सिंद्धांत अथवा अधिकार के रूप में बिना किसी लागत के शामिल होना चाहिए ।

-सहायता को आवश्यकता के अनुसार देना चाहिए न कि किसी विशिष्ट आपदा तक सीमित होना चाहिए - सूनामी के मामले में झगड़ों से प्रभावित लोगों को भी सहायता प्रतिक्रिया में शामिल करना चाहिए ।

अनुशंसा-3 स्वीकृत वातावरण व प्रासंगिक योगदान

-लोगों को आपदाओं के लिए उनकी आकस्मिक योजनाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सामग्री की प्राप्ति इस आधार पर हो कि गरीबों और सीमांत समूहों के लिए पर्याप्त प्रावधान हो । इसका विस्तार शिष्ट समाज संगठनों तक होना चाहिए, जिसमें स्त्रियों के समूह भी शामिल हों ।

-आपदाप्रद देशों की राष्ट्रीय सरकारों को आपदा प्रबंधन की व्यापक योजनाएं व कार्यनीतियां बनानी चाहिए जिसमें सूचना प्रबंधन भी शामिल हो जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदायों को प्रतिक्रिया के हर स्तर के बारे में पूरी तरह से सूचित कर दिया गया है ।

-आपदा प्रतिक्रियाओं के प्रबंधन हेतु केवल केंद्रीय निकायों की स्थापना ही नहीं करनी चाहिए, अपितु विभागों व केंद्रीय तथा स्थानीय सरकार के विभागों के बीच सहयोग करने योग्य होना चाहिए ।

-जो आपदा की प्रतिक्रिया से संबंधित हैं उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यों की पूर्ण सूचना सभी प्रभावित लोगों को उपलब्ध है, विशेष रूप से स्थानीय

समुदाय को । इसमें वित्तीय सूचना देते हुए लोक सूचनाओं एवं लोक अंकेक्षण को शामिल किया जा सकता है ।

-एजेंसियों को हितप्रहरी आंदोलन को मजबूत करना चाहिए तथा जनसंपर्क साधनों का समर्थन करना चाहिए जिससे प्रतिक्रिया की अच्छी समझ और प्रतिपुष्टि एवं बातचीत के अवसरों के द्वारा निम्न स्तर की जबावदेही को बढ़ाया जा सके ।